भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट | 21वीं सदी के सरकारी स्कूल, सुविधाएं आदिम युग जैसी

राज्य में स्कूल शिक्षा को लेकर मंत्रियों के सवालों का जवाब तलाशने भास्कर रिपोर्टर्स ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के हालात जानें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी भी है और चिंता भी।

मंत्रियों के बयान; शिक्षकों के साथ सरकार पर भी सवाल

विनोद मित्तल. जयपुर | मंत्रियों ने शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर बयान दिए। सही मायनों में सरकारी स्कूलों का सच बताया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं, शुरू होती है। सवाल उठता है-आखिर क्या वजह है कि मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी शिक्षकों के पढ़ाए बच्चे मेरिट में नहीं आते। दरअसल, मंत्री शिक्षा के गिरते स्तर पर सवाल तो उठाते हैं, पर सुधार के लिए कुछ नहीं करते। मंत्रियों के ये बयान शिक्षकों ही नहीं, सरकार की भी व्यवस्था पर सवाल हैं। स्थिति यह है कि राज्य के किसी सरकारी स्कूल में एक भी मंत्री या अफसर का बच्चा नहीं पढ़ता। सरकार ने शिक्षा सुधार के नाम पर 17,129 स्कूलों का एकीकरण तो कर दिया, पर इससे हालात नहीं बदले। **आखिर सच क्या है? पढ़िए भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट...**

मंत्रियों ने सिस्टम पर सिर्फ सवाल उठाए, पर किया क्या? क्या वे नहीं जानते ये सच...

सरकारी स्कूलों के कामकाज का सच चार पहलुओं पर	बजट	वेतन	काम	रिजल्ट
	11924.97	40 से 70,000	150 दिन	**शून्य...** क्योंकि सरकारी स्कूल क्वालिटी एजूकेशन तो छोड़िए, छात्रों को बुनियादी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे और ये तथ्य सर्वज्ञात है
	करोड़ रु. प्राथमिक-माध्यमिक का बजट राशि हर साल करीब 100 करोड़ बढ़ रही है	रुपए औसत वेतन है सरकारी शिक्षकों का, बड़े पदों पर और भी अधिक	वर्ष में। बाकी दिन मौसमी, त्योहारी, सरकारी, साप्ताहिक छुट्टियां	

बयान बहादुर जो बोले बहुत, किया कुछ नहीं

'अखबार पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं शिक्षक'

कालीचरण सराफ, शिक्षा मंत्री

142 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन वहां 252 शिक्षक लगे हैं। वे अखबार पढ़ने जाते हैं। 50-60 हजार का वेतन लेते हैं।

पांच साल में हालात ऐसे रहे कि आईएएस, सीए में टॉपर विद्यार्थी अगर राजस्थान में पढ़ाई करते तो टॉपर नहीं बन पाते।

शिक्षकों को सच स्वीकार करना होगा। वे अच्छी सैलेरी लेने के बावजूद परिणाम अच्छे नहीं दे रहे हैं।

'शिक्षक शादी में भी स्कूल खाते से जाते हैं'

गुलाबचंद कटारिया, पंचायतीराज मंत्री

शिक्षक जीमन, अंतिम संस्कार व शादी ब्याह में जाने का काम भी स्कूल के खाते से करते हैं। सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले तिगुना वेतन मिल रहा है, फिर भी वे समर्पित नहीं हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं।

पहली से आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने के लिए आरटीई में किया गया प्रावधान विदेशियों का षड्यंत्र है।

सरकारी स्कूलों का परिणाम देखकर मन व्यथित होता है। मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। बैकफुट पर आने वाला नहीं हूं।

शिक्षण व्यवस्था पर ये सवाल मंत्रियों ने अलग-अलग मौकों पर उठाए।

इतने खराब हालात : एक हॉल, पांच क्लासें, 120 बच्चे

अजमेर के राजकीय मॉडल उच्च मा. विद्यालय के एक ही हॉल में पांच कक्षाएं लग रही हैं।

प्रदेशभर में शिक्षा के बदहाल हालात » पेज 13

सच जो डराता है.

35% से कम रिजल्ट
रहा बोर्ड परीक्षा में 1643 स्कूलों (606 सी. सैकंडरी, 1037 सैकंडरी) का इस साल।

2 साल में
सरकारी स्कूलों के सिर्फ 8 बच्चे ही मेरिट में (2012-13, 13-14)

1 लाख
से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं पूरे राज्य में।

2089 स्कूल
में सिर्फ एक कमरा, जिनमें कक्षा 1 से पांच या आठवीं तक की पढ़ाई।

2537 स्कूल
किराए के भवनों में चल रहे हैं, 1313 स्कूल बिना भवन के।

नाउम्मीदी की पाठशाला, उम्मीदों का युद्धघोष कब?

भास्कर दृष्टिकोण

लक्ष्मी प्रसाद पंत

जरा देखिए, उम्मीद और नाउम्मीदी के दो चेहरे। आप इसे आशा और हताशा भी कह सकते हैं।

तमिलनाडु: सकारात्मक परिवर्तन की एक उम्मीद। इरोड जिले के कलेक्टर डॉ. आर आनंदकुमार ने अपनी 6 साल की बेटी गोपिका को कुमालनकुट्टई गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया ।

***मकसद:** कलेक्टर बताना चाहते थे कि उनके जिले के सरकारी स्कूल पढ़ाई के मामले में प्राइवेट स्कूलों से भी आगे हैं।*

राजस्थान: सिर्फ निराशा और अविश्वास। जैसे गणित बच्चों के लिए बेहद डरावना विषय होता है, वैसे ही सरकारी स्कूलों की पूरी पढ़ाई यहां आतंकित करती है। डर इस कदर कि न नेता न किसी अफसर का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है ।

***नतीजा:** भावनात्मक लगाव तो छोड़िये, सुधार की चुनौती लेने को भी कोई तैयार नहीं है।*

अगर आप मजबूत जिगर के हैं तो शिक्षा विभाग में फैली अराजकता के एक-एक तथ्य को अब पढ़ते जाइए। 3850 सरकारी स्कूलों में भवन नहीं हैं। एक कमरे में आठ-आठ क्लास चलती हैं। 142 स्कूल तो ऐसे हैं जहां छात्र एक भी नहीं है लेकिन 252 टीचर हैं। कुछ स्कूलों में तीन छात्र हैं किंतु टीचर पांच से अधिक और 7216 स्कूल तो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं।

अब देखिए रिजल्ट... इस साल दसवीं में 108 बच्चे मेरिट में आए लेकिन सरकारी स्कूलों से केवल एक छात्र। यकीनन ये पीड़ादायी कथाएं निराश करती हैं। हैरानी ये है कि इतनी खामियों के बावजूद न शिक्षाविद् बेचैन हैं, न सरकार।

बेशक यह इक्कीसवीं सदी है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल अब भी 19वीं सदी जैसे ही हैं। हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे बच्चों का दुर्भाग्य यह है कि उनके स्कूल से बाहर की दुनिया 4जी तक जा पहुंची है। लेकिन वहां सुधार अभी टूटी-फूटी बैलगाड़ी पर बेरफ्तार धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं। सदी गुजर गई है लेकिन शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बदलाव का इंतजार खत्म नहीं हुआ। हुक्मरान जाने कब समझेंगे कि सामाजिक बदलावों की शुरुआत तो स्कूलों से ही होनी चाहिए। स्कूलों में बजती घंटियां ही प्रगति के सुर हैं। लेकिन अफसोस, प्राथमिक शिक्षा में जो सुधार हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए था उसे आखिरी पायदान पर धकेल दिया गया है।

सरकार के दावों से उलट सरकारी स्कूलों के हालात अब भी 19वीं सदी जैसे ही हैं। बात मेक इन इंडिया की हो रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में कहीं छतें टपकती हैं तो कहीं प्लास्टर गिर रहा है, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी-टेबल भी नहीं हैं। तीन-तीन कक्षाएं एक पेड़ के नीचे लगती हैं। ये हालात देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि...

ऐसे सरकारी स्कूलों में कैसे पूरे होंगे इन आंखों के सपने

तस्वीर कोटड़ा (अजमेर) के राजकीय मा. विद्यालय की है। यहां कक्षाएं 10, कमरे सिर्फ छह हैं। एक में दफ्तर, एक में स्टोर है। बाकी बचे चार कमरों में स्कूल चल रहा है। बच्चों को स्टोर ... बिछाकर ... पढ़ाया जा रहा है।

भास्कर टीम | प्रदेश के विभिन्न अंचलों से

राज्य में सरकारी स्कूलों पर खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पांचवीं और आठवीं कक्षा वाले स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं हैं। शिक्षकों को भी कुर्सी बमुशिकल ही मिलती है। पेड़े के नीचे, बरामदे या ऊबड़-खाबड़ जमीन पर ही बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 हजार स्कूलों में टॉयलट नहीं है और 55 हजार स्कूलों में अब तक विद्युत कनेक्शन ही नहीं हुए हैं। एक लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। कई स्कूलों में छात्र नहीं हैं तो कई जगह शिक्षक नहीं मिलते हैं। किसी स्कूल की छत नहीं है तो कहीं स्कूल भवन जर्जर हो रहे हैं। कक्षाओं में बारिश का पानी टपकता है। कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में तो गांव के ही लोग चंदा करके शिक्षकों का इंतजाम कर रहे हैं।

स्कूलों के ऐसे हालात

जिन स्कूलों में एक से 15 तक बच्चों का नामांकन हुआ है, ऐसे 8164 स्कूल हैं, जिनमें 14655 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसी तरह जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 16 से 30 ही है, ऐसे 19707 स्कूल हैं जिनमें 42150 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।

विषय पढ़ाने वाले व्याख्याता ही नहीं

राज्य में अभी 4456 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में व्याख्याता के 32090 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 14408 व्याख्याता कार्यरत हैं और 17682 पद रिक्त पड़े हैं।

मॉनिटरिंग के लिए नहीं हैं बड़े अफसर

शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक के 2 पद हैं, दोनों ही खाली पड़े हैं। संयुक्त निदेशक के 9 पद हैं, सभी खाली हैं। उपनिदेशक के 36 पद हैं, लेकिन केवल 1 पद भरा है। जिला शिक्षा अधिकारी के 142 पद स्वीकृत हैं। इसमें से केवल 32 डीईओ ही कार्यरत हैं।

क्रमोन्नत हो रहे हैं स्कूल, पद खाली

शिक्षा विभाग में वर्तमान में 1,02,677 पद खाली पड़े हैं। इसमें 50,450 माध्यमिक शिक्षा के और 52,227 पद प्रारंभिक शिक्षा के हैं। माध्यमिक शिक्षा में प्रिंसिपल के 1878, हैडमास्टर के 3637, व्याख्याता के 17633, शारीरिक शिक्षकों के 778, सेकंड ग्रेड के 19971 और तृतीय श्रेणी के 6553 पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा में सेकंड ग्रेड के 11492, थर्ड ग्रेड के 39718 और शारीरिक शिक्षकों के 1017 पद खाली पड़े हैं।

शिक्षा और शिक्षकों के वेतन पर बढ़ता खर्च, गिरता परिणाम

क्वालिटी एज्युकेशन में हम कहां?

लर्निंग लेवल में भी पिछड़े

तीसरी से पांचवीं के लर्निंग लेवल में राजस्थान 20 वें स्थान पर और छठी से आठवीं तक के बच्चों के लर्निंग लेवल के मामले में 13वें स्थान पर है।

प्रारंभिक शिक्षाः 29 वें स्थान पर

प्रारंभिक शिक्षा के मामले में 238 अंकों के साथ राजस्थान 29वें नंबर पर है। त्रिपुरा पहले व 226 अंकों के साथ छतीसगढ़ अंतिम पायदान पर है।

गणित में 31 वें स्थान पर

236 अंक, 31 वां स्थान। इस मामले में 279 अंकों के साथ दमन एवं दीव पहले व 22 अंकों के साथ छतीसगढ़ आखिरी पायदान पर है।

17 हजार स्कूल मर्ज के नाम पर बंद किए

- विभाग ने चालू सत्र में 17129 स्कूलों को बंद कर दिया।
- इन 17129 स्कूलों में 14967 प्राथमिक स्कूल, 2139 उच्च प्राथमिक स्कूल और 23 माध्यमिक स्कूल हैं।
- इन स्कूलों को 3856 उच्च माध्यमिक स्कूल, 7074 माध्यमिक स्कूल, 1709 उच्च प्राथमिक स्कूल और 897 प्राथमिक स्कूल यानी कुल 13536 स्कूलों में मर्ज किया गया है।

यूं बढ़ता जा रहा है खर्च (करोड़ रुपए)

	प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	सालाना खर्चा
2012-13	7427.36	4497.61	11924.97
2011-12	6689.97	3937.70	10627.67
2010-11	5850.06	3435.40	9285.46

प्रति विद्यार्थी बढ़ रहा है खर्चा

	प्रारंभिक	माध्यमिक
2010-11	9908	15391
2011-12	11247	15782
2012-13	13058	17721

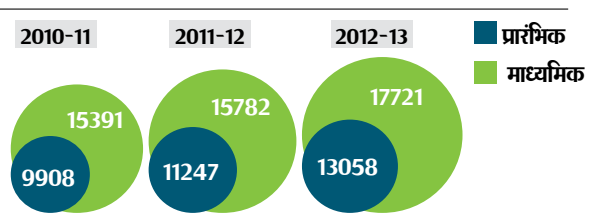

शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खर्च करती है सरकार

राज्य सरकार से शिक्षकों को अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है। जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) ये ही काम कर रहे हैं।

और यूं गिरता जा रहा है परिणाम

बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट में पिछड़े सरकारी स्कूल, दो साल में 273 मेरिट, सरकारी स्कूलों के सिर्फ 8 स्टूडेंट

2014: मेरिट में सरकारी छात्र

संकाय	कुल	सरकारी	प्राइवेट
वाणिज्य	14	1	13
विज्ञान	23	0	23
कला	19	2	17
10वीं	108	1	107

2013: मेरिट में सरकारी छात्र

संकाय	कुल	सरकारी	प्राइवेट
वाणिज्य	25	1	24
विज्ञान	15	0	15
कला	18	1	17
10वीं	51	2	49

ये कमियां हैं हमारे तंत्र में

एक लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सी. सैकंडरी स्कूलों में विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं, टॉयलेट व बिजली कनेक्शन भी नहीं हैं

पद हैं खाली

फिजिक्स-कैमिस्ट्री के लैक्चरर नहीं

विषय	कुल पद	कार्यरत	रिक्त पद
फिजिक्स	1272	665	607
कैमिस्ट्री	1292	697	595
बॉयोलॉजी	883	433	450
गणित	737	236	501
होम साइंस	450	192	258
कॉमर्स	2907	1181	1726
हिंदी	6783	3121	3663
अंग्रेजी	4452	2015	2437

टॉयलेट ही नहीं

2224 गर्ल्स स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं हैं राज्य में

2990 स्कूलों में टॉयलेट हैं, लेकिन काम के नहीं हैं

बिजली ही नहीं

55519 स्कूलों में विद्युत कनेक्शन ही नहीं है राज्य के 84661 सरकारी स्कूलों में से

2089 स्कूलों में एक कमरा है

52872 स्कूलों में खेल मैदान नहीं

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट

प्रारंभिक शिक्षा में जिलेवार थर्ड ग्रेड के रिक्त पद

जिला	रिक्त पद
उदयपुर	3228
बाड़मेर	3005
नागौर	2354
जोधपुर	2243
जयपुर	2226
अजमेर	821
टोंक	756
भीलवाड़ा	1525
कोटा	318
बारां	895
बूंदी	512
झालावाड़	727
सीकर	1083
दौसा	641
अलवर	1153
भरतपुर	1203
धौलपुर	1211
करौली	634
स माधोपुर	592
बीकानेर	1267
चूरू	757
झुंझुनूं	728
गंगानगर	1153
हनुमानगढ़	666
पाली	859
जैसलमेर	1192
जालौर	1792
सिरोही	605
राजसमंद	502
चित्तौड़गढ़	1142
प्रतापगढ़	1219
डूंगरपुर	1300
बांसवाड़ा	1409

भामाशाह दे चुके हैं डेढ़ अरब रुपए दान

राज्य में अब तक 20 बार हुए भामाशाह सम्मान समारोह में 1165 भामाशाहों को सम्मानित किया जा चुका है। इन भामाशाहों ने 14,092.10 लाख रुपए विभाग को दान किए हैं।

सचाई बयां करती ये तस्वीरें

पेड़-टैंट ही सहारा

1. कोटा. किशोरपुरा में पेड़ के नीचे रोज यूं लगती है क्लास। **2.** भीलवाड़ा. राउप्रावि जसवंतपुरा में कमरे कम होने के कारण स्कूल में टैंट के नीचे पढ़ते हैं बच्चे। **3.** भीलवाड़ा. बनेड़ा में बेसकलाई के स्कूल में पेड़ के नीचे दो कक्षाओं को साथ पढ़ाते दो शिक्षक।

बरामदों में क्लास

1. कोटा के किशोरपुरा राउप्रावि में जिस हॉल में बच्चे पढ़ते हैं। वहीं पर खाना बनाया जाता है। **2.** भीलवाड़ा. कोटड़ी में चमारों का झोपड़ा गांव में स्कूल भवन नहीं है। यहां पढ़ाई खुले में होती है।

बांसवाड़ा. राजकीय प्रा. विद्यालय फतेहपुरा की इमारत जर्जर हो चुकी है। इसके ढहने का खतरा रहता है।

हालात चिंताजनक

पहली में दाखिला लेने वाले 100 में से 27 बच्चे ही पहुंच पाते हैं 12वीं तक

राजस्थान में प्राइमरी लेवल पर ड्राप आउट रेट 33.22 प्रतिशत है। यही नहीं पहली कक्षा में प्रवेश के बाद बारहवीं तक पहुंचने वाले बच्चों के मामले में राजस्थान में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अगर राज्य में पहली कक्षा में 100 बच्चे प्रवेश लेते हैं तो उनमें से 54 बच्चे ही 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते तो इन बच्चों की संख्या 27 ही रह जाती है। जो पहली कक्षा के मुकाबले लगभग चौथाई संख्या है। उच्च कक्षा में प्रवेश के मामले में भी स्थिति बहुत खराब है। अगर 100 बच्चे बारहवीं पास करते हैं तो उनमें से 12 फीसदी ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले पाते हैं। राज्य में 27 बच्चे बारहवीं में आते हैं। बारह फीसदी के हिसाब से देखा जाए तो राज्य में यह संख्या 4 ही आती है।

पढ़ाई के लिए मिलते हैं केवल 5 महीने

सरकारी स्कूलों में एक सत्र में पढ़ाई के लिए शिक्षकों को केवल 5 महीने का समय ही मिलता है। गर्मी की छुट्टियों के 45 दिन, शीतकालीन अवकाश के 7 दिन, दीपावली अवकाश के 12 दिन, शैक्षिक सम्मेलन के 4 दिन, रविवार 52, त्योहारों के 30 से 40 दिन, तेज सर्दी या गर्मी से छुट्टी करीब 10 दिन, प्रथम व द्वितीय जांच, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के कारण 30 दिन, गैर शैक्षिक कार्य के कारण 20 से 30 दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके अलावा कलेक्टर पावर, शिक्षक के पूर्व निर्धारित अवकाश जिसमें 15 आकस्मिक व 15 उपार्जित अवकाश के कारण भी पढ़ाई नहीं हो पाती है।

सालभर करते हैं गैर शैक्षिक काम : शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगी रहती है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण बीएलओ, सर्वे, पल्स पोलिया, जनगणना, पशु गणना, बाल श्रमिक गणना, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य कार्य करते रहते हैं।

सरकारी स्कूलों को संकट से कैसे उबारें? अपनी राय 9672977751 पर एसएमएस करें

ग्राफिक्सः रमन कांत शर्मा